

भोपाल में साइबर ठगों का 'आतंक', 24 घंटे में 25 शिकार, खातों से उड़े 15 लाख रुपये से ज्यादा

कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

भोपाल। राजधानी में साइबर जालसाज अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में साइबर ठगी के 25 मामले सामने आए हैं। जिसमें पीड़ितों से 15 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई। किसी को बैंक के क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर झांसा दिया गया, तो किसी को सीआरपीएफ अधिकारी का सामान सस्ते में दिलाने और कपड़े वापस कराने के बहाने ठगा गया। जालसाजों ने मोबाइल का एक्सेस लेकर और यूपीआइ ट्रांजेक्शन के जरिए खातों से रकम निकाल ली। पिपलानी के सोनागिरी निवासी भेल कर्मचारी कमलेश कुमार पटेल को 22 सितंबर को एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को बैंक के वेरिफिकेशन विभाग का कर्मचारी बताया। आरोपित ने एसबीआई और फेडरल बैंक के क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन करने के नाम पर कार्ड की जानकारी ली और गूगल पर कुछ सर्च करने को कहा। इसके बाद मोबाइल का एक्सेस उसके हाथ में चला गया। कुछ देर में फेडरल बैंक से 90 हजार और एसबीआई से 90-90 हजार रुपये की दो ट्रांजेक्शन कर कुल 2.70 लाख रुपये निकाल लिए गए। शाहपुरा निवासी नरेंद्र रैकवार के आइडीबीआई बैंक खाते से 24 और 25 सितंबर को गूगल पे के जरिए ठगी की गई। जालसाजों ने 30-30 हजार रुपये की तीन और 22 हजार रुपये की एक ट्रांजेक्शन कर कुल 1.12 लाख रुपये निकाल लिए। नरेंद्र को खाते से रकम निकलने की जानकारी 28 सितंबर को हुई। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की। पुलिस इस हत्याकांड को केवल आपसी विवाद के तौर पर नहीं देख रही है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी घर से कीमती सामान और नकदी लेकर भागा है। इसके साथ ही मृतक राकेश अग्रवाल के कुछ लोगों के साथ हुए आर्थिक लेन-देन की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस हत्या के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए लूट, लेन-देन और आरोपी के संपर्कों को जोड़कर कड़ियां मिला रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या की असल वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी।

अमित शाह के दौरे के चलते शाम 6 बजे से बदलेगा रूट, भारी वाहन और बसें की जाएंगी डायवर्ट

भोपाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शुक्रवार 2 अक्टूबर को भोपाल भ्रमण के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। स्टेट हैंगर से होटल ताज तक उनके आवागमन के चलते शाम 6 बजे से यात्री बसों और भारी वाहनों के रूट डायवर्ट किए जाएंगे। वहीं, रात 8 बजे से सामान्य दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग लागू होंगे।सीहोर और उज्जैन की ओर से आने-जाने वाली यात्री बसें हलालपुर बस स्टैंड से आगे लालघाटी नहीं जा सकेंगी। राजगढ़-ब्यावरा से हलालपुर आने वाली बसें मुबारकपुर बायपास, खजूरी बायपास और बैरागढ़ होकर पहुंचेंगी। नादरा बस स्टैंड जाने वाली बसें मुबारकपुर, गांधीनगर, करौंद, बेस्ट प्राइज और जेपी नगर होकर चलेंगी। भदभदा चौराहा से भारत माता चौराहा, स्मार्ट रोड, पालीटेक्निक, कमलापार्क, रेतघाट, वीआईपी रोड, लालघाटी और गांधीनगर तक भारी, मालवाहक, व्यावसायिक और अनुमति प्राप्त वाहनों का आवागमन बदला रहेगा। इनके लिए नेहरू नगर, भदभदा, नीलबड़, नाथू बरखेड़ा, मुगालिया छाप और खजूरी बायपास का वैकल्पिक मार्ग रहेगा। बैरागढ़, एयरपोर्ट और राजगढ़-ब्यावरा जाने वाले वाहन नेहरू नगर, भदभदा, नीलबड़ और खजूरी बायपास होकर जा सकेंगे। सीहोर-इंदौर के लिए रातीबड़ और झागरिया का रास्ता रहेगा। शहर से सीहोर, इंदौर, राजगढ़-ब्यावरा और एयरपोर्ट जाने वाले वाहन प्रभात चौराहा, जेके रोड, रत्नागिरी, अयोध्या बायपास, भानपुर और करौंद होकर निकल सकेंगे। एंबुलेंस और दमकल वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण के लिए 4470.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति

प्रदेश के समग्र विकास और जनहित को गति देने के लिए 24 हजार 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश की राशि प्रदाय करने के लिए 348 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति

अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्रदाय करने के लिए 5 हजार 329 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति

सिंगरौली में 605 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय निर्माण के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

भोपाल,जसं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जनहित को गति देने के लिए लगभग 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी। युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मंत्रि-परिषद ने पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसी वर्दीधारी सेवाओं में



अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए 5,329.17 करोड़ रुपये, स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश राशि के लिए 348 करोड़ 7 लाख रुपये तथा स्वास्थ्य केंद्रों व औषधि नियंत्रण के लिए 3,245 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। अधोसंरचना विस्तार के तहत 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से दमोह-कटनी 4-लेन मार्ग निर्माण, ग्रामीण विकास निधि के लिए 3,580 करोड़ 22 लाख रुपये और सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत उज्जैन की कान्ह डायवर्सन परियोजना सहित दतिया, नीमच व सागर की बंडा वृहद सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय प्रदेश में रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को गति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की युवाओं को सशक्त बनाने की मंशा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत

आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार अब गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)की भर्ती में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह गृह विभाग अंतर्गत विशेष सशस्त्र बल में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों 20 प्रतिशत, जेल विभाग अंतर्गत जेल प्रहरी में होमगार्ड को 15, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी आरक्षक में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण (हॉरिजेन्टल) दिये जाने का निर्णय लिया गया है।मंत्रि-परिषद ने सत्र 2026-27 में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के लिये गणवेश की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्र, छात्राओं और पालकों के खातों में प्रदाय करने के लिए 348 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्रदाय करने के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय प्रदाय संबंधी योजना को आगामी 5 वर्षों 2026-27 से 2030 -31 तक निरंतर संचालन के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। प्रदेश के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में शिक्षकों के विषयमान से स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन की व्यवस्था की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत है। मंत्रि-परिषद ने जिला चिकित्सालय सिंगरौली में अतिरिक्त 155 बिस्तरों की वृद्धि करते हुए 450 से 605 बिस्तरीय चिकित्सालय में विस्तार कार्य के साथ आंतरिक और बाह्य विकास कार्यों तथा बायोमेडिकल उपकरण एवं अस्पताल फर्नीचर आदि कार्य के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में जिला चिकित्सालय सिंगरौली के परिसर में 400 बिस्तरीय अस्पताल भवन एवं 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के एकजार्ड भवन निर्माण कार्य के लिए 188 करोड़ 72 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इंदौर में बनेगा 15 करोड़ का सिंधु कला केंद्र

भोपाल में रिटायर्ड IAS मर्डर केस में बड़ा खुलासा, गैस सिलिंडर खोलकर आग लगाने की कोशिश... 2KM पैदल भागा केयरटेकर

कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

भोपाल। भोपाल के रातीबड़ इलाके के सूरज नगर में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी लीड मिली है। पुलिस ने आरोपी केयर टेकर वरुण कुमार के भागने का पूरा रूट ट्रेस कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रात के अंधेरे में ही ट्रेन पकड़कर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की दर्जनभर टीमें तैनात की गई हैं।

रात 12:30 से 2 बजे के बीच हुई वारदात, गैस खोलकर आग लगाने की कोशिश

पुलिस जांच के अनुसार, 30 सितंबर की रात रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल अपने कमरे में सो रहे थे। रात करीब 12:30 से 2:00 बजे के बीच आरोपी ने धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने या घर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से रसोई के गैस सिलेंडर का पाइप निकाल



दिया और आग लगाने का प्रयास किया। मृतक की पत्नी निशी अग्रवाल का कमरा आरोपी ने बाहर से बंद कर दिया था। सुबह करीब 4:40 बजे जब उनकी नींद खुली तो दरवाजा बाहर से लॉक मिला। इसके बाद घर के कर्मचारी अमर की मदद से दरवाजा खोला गया, तब जाकर इस सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। पुलिस को मौके पर संघर्ष के निशान भी मिले हैं।

2 किमी पैदल चला, फिर ऑटो से पहुंचा भोपाल रेलवे स्टेशन

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी के भागने की पूरी कहानी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक रात 2:40 बजे आरोपी घर से बाहर निकला। घटना स्थल से 200 मीटर दूर लगे कैमरों में वह हाथ में एक पिट्टू बैग और एक झोला लिए हुए दिखाई दिया। लगभग 2 किलोमीटर पैदल

चलने के बाद वह भदभदा चौराहा पहुंचा और वहां से एक ऑटोरिक्षा लिया। ऑटो पॉलीटेक्निक चौराहा और कमला पार्क होते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन की ओर गया। स्टेशन से कुछ दूर पहले उतरकर वह पैदल भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से होकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा। रात 3:30 बजे वह दिल्ली लाइन की ट्रेन में सवार होकर निकल गया। अब पुलिस झांसी, ग्वालियर और आगरा रूट के स्टेशनों के CCTV फुटेज खंगाल रही है।

प्लेसमेंट एजेंसी और पुलिस वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

जांच में सामने आया है कि आरोपी को 'वर्मा होम हेल्थ केयर' एजेंसी के जरिए नौकरी पर रखा गया था। यह एजेंसी बाग सेवनिया के विश्वकर्मा नगर में स्थित है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही

है कि एजेंसी ने उसका अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था या नहीं। यदि नियमों की अनदेखी पाई गई तो एजेंसी संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी का पंजाब के पटियाला एसपी कार्यालय से 1 मई 2025 को जारी एक चरित्र प्रमाण पत्र भी सामने आया है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसे नौकरी पर रखा गया था। भोपाल पुलिस ने पंजाब पुलिस से भी उसके पुराने बैकग्राउंड और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है।

लूट और आर्थिक लेन-देन के एंगल से भी जांच

पुलिस इस हत्याकांड को केवल आपसी विवाद के तौर पर नहीं देख रही है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी घर से कीमती सामान और नकदी लेकर भागा है। इसके साथ ही मृतक राकेश अग्रवाल के कुछ लोगों के साथ हुए आर्थिक लेन-देन की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस हत्या के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए लूट, लेन-देन और आरोपी के संपर्कों को जोड़कर कड़ियां मिला रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या की असल वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी।

गांधी जयंती : जहां विवाद थाने नहीं, चौपाल तक पहुंचते हैं, ‘सीताराम’ से शुरू होती है सुबह, मुकदमों से दूर खरगोन का गांव कठोरा

कोबरा डॉट कोम । न्यूज़

खरगोन।यहां आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा प्रासंगिक है... जी हां हम बात कर रहे हैं जिले के एक छोटे से गांव की। नर्मदा के किनारे बसा कठोरा गांव सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक निर्णय की ऐसी मिसाल है, जिसकी चर्चा देश के सर्वोच्च न्यायालय तक दो बार पहुंची है।

यहां विवाद होते हैं, मतभेद भी होते हैं, लेकिन उन्हें थाने और अदालत तक ले जाने के बजाय ग्रामीण अपनी चौपाल पर बैठकर सुलझा लेते हैं। यही परंपरा इस गांव को वर्षों से विवादविहीन बनाए हुए है। गांव को वर्ष 2002 में पहली बार विवादविहीन गांव का सम्मान मिला था। इसके 18 वर्ष बाद वर्ष 2020 में तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने ग्रामीणों से आनलाइन संवाद कर गांव को डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किया था। खरगोन : यहां आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा प्रासंगिक है... जी हां हम बात कर रहे हैं जिले के एक छोटे से गांव की। नर्मदा के किनारे बसा कठोरा गांव सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक निर्णय की ऐसी मिसाल है, जिसकी चर्चा देश के सर्वोच्च न्यायालय तक दो बार पहुंची है। यहां विवाद होते हैं, मतभेद भी होते हैं, लेकिन उन्हें थाने और अदालत तक ले जाने के बजाय ग्रामीण अपनी चौपाल पर बैठकर सुलझा लेते हैं। यही परंपरा इस गांव को वर्षों से विवादविहीन बनाए हुए है। गांव को वर्ष 2002 में पहली बार विवादविहीन गांव का सम्मान मिला था। इसके 18 वर्ष बाद वर्ष 2020 में तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने ग्रामीणों से आनलाइन संवाद कर गांव को डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किया था।

गांव में मुख्य रूप से किसान और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं

गांव पटेल देवराम पटेल, रामसिंह यादव व कड़वा यादव बताते हैं कि कठोरा में सामाजिक संरचना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां किसी विवाद को व्यक्ति या परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल बनाने के बजाय सामुदायिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश होती है। गांव में मुख्य रूप से किसान और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं।

खरगोन में दो गायों की करंट से मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राजमार्ग पर पांच घंटे दिया धरना, लगी वाहनों की लंबी कतारें

कोबरा डॉट कोम । न्यूज़

खरगोन। शहर के बिस्टान रोड पर शनिवार सुबह दो गाएँ बिजली के टूटे तारों की चपेट में आ गईं। तारों में करंट होने से गायों ने मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे गोरक्षकों ने विद्युत वितरण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी दर्ज कराई।

दोपहर करीब 12 बजे मृत गायों को लेकर गोरक्षक कसरावद रोड स्थित अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यालय के सामने चित्तौड़गढ़-भुसावल राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाय के शव रखकर प्रदर्शन किया। इससे राजमार्ग पर रास्ताजाम की स्थिति निर्मित हो गई। सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए।

वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा

हालांकि दोपहर करीब दो बजे एक एबुलेंस के आने पर गोरक्षकों ने उसे निकलने का रास्ता दिया। करीब पांच घंटे चले प्रदर्शन के बाद विभाग ने बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आनन-फानन में लापरवाही के जिम्मेदार विद्युतकर्मों को निलंबन करने का आदेश जारी किया। उधर, जाम के चलते विविक्त कार्यालय के पीछे से मार्ग डायवर्ट करने पर वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। निर्माणाधीन कालोनी में



दोनों वर्गों के लोग विवाद की स्थिति में चौपाल पर बैठते हैं

दोनों वर्गों के लोग विवाद की स्थिति में चौपाल पर बैठते हैं और बातचीत के जरिए समाधान तलाशते हैं। किसी एक पक्ष की जीत के बजाय संबंधों को बचाए रखना प्राथमिकता होती है। पारिवारिक या महिलाओं से जुड़े विवादों में गांव की महिलाएं स्वयं आगे आती हैं। वे संबंधित परिवारों से बातचीत कर मामले को समझती हैं और आपसी सहमति से समाधान निकालने का प्रयास करती हैं। इस व्यवस्था ने कई छोटे विवादों को बड़ा रूप लेने से पहले ही रोकने में भूमिका निभाई है। चौपाल पर होने वाली बातचीत, महिलाओं की भागीदारी, नर्मदा तट की आध्यात्मिकता और ‘सीताराम’ से शुरू होने वाला दिन, इन सबने मिलकर कठोरा को महज एक गांव नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द की जीवंत परंपरा बना दिया है। छोटे-बड़े मामले गांव की चौपाल पर ही निपटाने की परंपरा आजादी के पूर्व से ही गांव के बुजुर्गों ने शुरू की थी। वर्तमान के युवा व बच्चे भी गांव की परंपरा को निभा रहे हैं।

एक गांव, दो बार मिला प्रमाण-पत्र

ग्राम के युवा पवन यादव ने बताया कि कठोरा की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि विवादविहीन गांव का गौरव उसे एक बार नहीं, बल्कि दो बार मिला। वर्ष 2002 में गांव को यह पहचान मिली थी। इसके बाद भी ग्रामीणों ने अपनी सामाजिक परंपरा को बनाए रखा और वर्ष 2020 में गांव को दूसरी बार यह सम्मान मिला। तत्कालीन सीजेआइ शरद अरविंद बोबडे ने आनलाइन ग्रामीणों से बातचीत कर उनके

वाहनों की कतार में एक एंबुलेंस वाहन भी बहुत देर तक फंसा रहा। विविक्त के अधीक्षण यंत्री जयपाल ठाकुर ने गोरक्षकों के बीच पहुंचकर उन्हें बताया कि लापरवाही बरतने पर खरगोन ग्रामीण विद्युत केंद्र पर पदस्थ लाईन परिचायक जितेंद्र भालसे को तत्काल प्रभावी निलंबित कर दिया है। आदेश की कापी सौंपते हुए रास्ताजाम खोलने की अपील की। इस दौरान एसडीएम सत्येंद्र बैरवा, तहसीलदार आदि अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। आदेश की कापी मिलने के बाद गोरक्षकों ने प्रदर्शन खत्म किया। इसके चलते शाम करीब 5.30 बजे आवागमन शुरू हो सका। हालांकि लंबा जाम होने के चलते करीब छह बजे यातायात सुचारु हो सका। इस दौरान यात्री बसों में सवारियां व स्कूल बसों में विद्यार्थी भी परेशान हुए।

यह था मामला

प्रदर्शन में शामिल गोमाता सेवा संस्थान अध्यक्ष गोरक्षक सतीष राठीड़, हरिओम यादव, कमलेश यादव ने नाराजगी दर्ज कराते हुए बताया कि करंट से मौत का यह कोई पहला मामला नही है। पिछले चार माह में यह तीसरी घटना है। इससे पहले डेढ़ माह पहले जून माह में भी मांगरूल रोड पर एक नंदी की करंट से मौत हो गई थी। विभाग की इस लापरवाही के खिलाफ पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके है, लेकिन विभाग

सामुदायिक विवाद निपटाने की व्यवस्था को जाना और डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

न जुआ-सट्टा, न ताश की चौपाल, भजन-कीर्तन में मिलता है सुकून

कठोरा की सामाजिक संस्कृति की दूसरी खासियत यहां की जीवनशैली है। ग्रामीण जुआ, सट्टा और ताश जैसी गतिविधियों से दूरी बनाए रखने को अपनी सामुदायिक परंपरा का हिस्सा मानते हैं। नर्मदा किनारे बसे गांव में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां लोगों के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शाम के समय मंदिरों में भजन-कीर्तन और सामूहिक धार्मिक आयोजन ग्रामीणों को एक साथ जोड़ते हैं।

तया बच्चे, तया बुजुर्ग सबका एक ही नाम ‘सीताराम’

ग्राम के वरिष्ठ शेरू यादव, कैलाश यादव व सुखदेव यादव बताते हैं कि यहां अधिवादन भी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि गांव की संस्कृति का हिस्सा है। ग्रामीणों के दिन की शुरुआत ‘सीताराम’ के नाम और एक-दूसरे को ‘राम-राम’ कहकर होती है। यहां बुजुर्ग, महिला-पुरुष व बच्चे भी एक-दूसरे से बात करते समय नाम के स्थान पर ‘सीताराम’ से ही संबोधित करते हैं। शायद यही वजह है कि कठोरा की चौपाल पर मतभेद के बावजूद मनभेद को स्थायी जगह नहीं मिलती। कठोरा की पहचान केवल सामाजिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। गांव में संत श्रीश्री 1008 नानकदास जी महाराज ने करीब 400 साल पहले धर्म की ऐसी अलख जगाई, जो आज तक प्रकाशमान है। नर्मदा तट स्थित संतश्री की जीवित समाधि भी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है।

गंभीर नहीं है। इसलिए आज इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखा।

पहले भी कर चुके प्रदर्शन

गोरक्षक ऋषि यादव, मनोज कर्मा व वीरेंद्र बडे ने बताया इससे पहले चार अगस्त को मुसेखां रोड पर भी एक गाय करंट की चपेट में आ गई थी। उस समय भी पोस्ट ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया था। बार-बार करंट से हो रही गोवंश की मौत के बाद भी विभाग लापरवाही बरत रहा है। गोरक्षकों का आरोप है कि बिस्टान रोड पर तार टूटने की सूचना लोगों ने शुक्रवार रात ही दे दी थी, बावजूद इसके न तो सप्लाय बंद की और न ही टूटे तार का दुरुस्ती कार्य किया गया। नतीजतन यह गायें इन करंट की चपेट में आ गईं। र्दर्शन के दौरान वाहनों से उपज लाए कई किसान भी जाम में फंस गए, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों से कहासुनी भी हुई। एक किसान ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ने लगा, जिससे विवाद बढ़ने पर मौके पर तैनात मेनगांव थाना प्रभारी मंशाराम रोमड़े ने किसानों सहित गोरक्षकों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। इस दौरान तैनात पुलिसकर्मियों ने नवग्रह मंदिर पुल, स्टाप डेम रपट, टेमला फाटो और मेनगांव थाने के सामने बेरिकेट्स लगाकर भारी वाहनों को रोका और छोटे वाहनों के मार्ग डायवर्ट किए।

मनमाड़-इंदौर रेल मार्ग को लेकर पटरी पर सपने : पांच हजार करोड़ की लागत से 72.66 किमी रेलखंड का टेंडर जारी



कोबरा डॉट कोम । न्यूज़

खरगोन। मालवा-निमाड़ को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से सीधे जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर नई ब्रॉडगेज रेल परियोजना के निर्माण की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। मध्य रेलवे के निर्माण संगठन द्वारा परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए लगभग 4930.91 करोड़ की लागत का ईपीसी ई-टेंडर जारी किया गया है। टेंडर के तहत डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) से ग्यासपुरखेड़ी तक 72.66 किलोमीटर लंबे रेलखंड का निर्माण किया जाएगा।

निर्माण कार्य को चार वर्ष में पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है

अनुबंध आवंटित होने के बाद इस पूरे निर्माण कार्य को चार वर्ष में पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस मार्ग पर 25 बड़े पुल, सात स्टेशन व चार आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) व सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रक्रिया आगे बढ़ने से मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में रेलमार्ग के सपने पटरी पर आए हैं। जानकारी अनुसार इस महत्वपूर्ण रेलखंड में कठिन पहाड़ी व

देवी अहिल्याबाई के जीवन और विरासत पर शोध को मिलेगा नया आयाम, होलकर कल्चरल सेंटर और FIHCR के बीच हुआ एमओयू

कोबरा डॉट कोम । न्यूज़

खरगोन। लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर के जीवन, नेतृत्व और ऐतिहासिक विरासत को प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर नई पीढ़ी और दुनिया के सामने लाने की दिशा में मंगलवार को शाम 5:30 महेश्वर में महत्वपूर्ण पहल हुई।अहिल्या फोर्ट में होलकर कल्चरल सेंटर (HCC) और फाउंडेशन फॉर इंडियन हिस्टॉरिकल एंड कल्चरल रिसर्च (FIHCR) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में होलकर कल्चरल सेंटर के संस्थापक-संरक्षक प्रिंस यशवंतराव होलकर और FIHCR के संस्थापक-निदेशक इतिहासकार डॉ. विक्रम सम्पत मौजूद रहे।

MoU का उद्देश्य अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक नेतृत्व, कार्यशैली और विरासत से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों, अभिलेखीय सामग्री तथा अन्य स्रोतों के शोधपरक अध्ययन को बढ़ावा देना है। FIHCR द्वारा मध्यप्रदेश संस्कृति संचालनालय के सहयोग से अहिल्याबाई के जीवन और नेतृत्व पर शोधपरक पुस्तक तैयार की जा रही है। इस सहयोग से होलकर परंपरा से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन में सहायता मिलने की उम्मीद है। प्रिंस यशवंतराव होलकर ने

मैदानी भू-भाग को देखते हुए बड़े पैमाने पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। जारी टेंडर के अनुसार इस रेल मार्ग पर 25 मेजर रेलवे पुल, अनेक माइनर ब्रिज, चार रोड ओवर ब्रिज व पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगों का निर्माण शामिल है।

एक बड़े और ऊंचे रेलवे वायडवट का भी निर्माण प्रस्तावित है

इसके अलावा एक बड़े और ऊंचे रेलवे वायडवट का भी निर्माण प्रस्तावित है। 72.66 किमी के हिस्से में कुल सात रेलवे स्टेशन प्रस्तावित बताए गए हैं। इसमें ग्यासपुरखेड़ी, चिकट्यावड़, नीमगढ़, सराय तालाब, झाड़ी बड़ौदा, कैलौद और कमदपुर शामिल है। जारी निविदा के अनुसार पहली प्री-बिड बैठक 30 नवंबर व दूसरी प्री-बिड बैठक 30 दिसंबर को होगी। ऑनलाइन बोली प्रक्रिया चार फरवरी 2027 से शुरू होगी और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2027 सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है। निविदा में भाग लेने वाली फर्मों के लिए लगभग 9.86 करोड़ रुपए की ईएमडी निर्धारित है।

कहा कि मां साहब अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर अब तक काफी इतिहास लिखा जा चुका है, लेकिन आज की पीढ़ी और विशेषकर युवाओं के लिए इस इतिहास को जीवंत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक और शोध का उद्देश्य केवल पुराने इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि शोध के माध्यम से मां साहब के जीवन, विचारों और कार्यों को नए स्वरूप में दुनिया के सामने लाना है। उन्होंने कहा कि FIHCR की टीम और होलकर कल्चरल सेंटर के सहयोग से होने वाला यह शोध एक प्रमाणिक और सुंदर दस्तावेज के रूप में सामने आएगा। महेश्वर स्वयं मां साहब के जीवन और कार्यों का जीवंत प्रमाण है। यहां उनके शासन, समाजसेवा, संस्कृति और लोककल्याण की दृष्टि को करीब से समझा जा सकता है। शोध और दस्तावेजीकरण के माध्यम से महेश्वर से जुड़े इस इतिहास को व्यापक वैश्विक संदर्भ में सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। FIHCR के संस्थापक-निदेशक डॉ. विक्रम सम्पत के नेतृत्व में शोध परियोजना संचालित हो रही है। FIHCR की प्रोग्राम मैनेजर रसिका भाले शोध प्रक्रिया में भूमिका निभा रही हैं। MoU के माध्यम से दोनों संस्थाओं के बीच ऐतिहासिक सामग्री और शोध संसाधनों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकाल लोक से पीएम ई-बस सेवा एवं उज्जैन दर्शन सेवा का किया शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने बस में सफर भी किया

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को प्रदेश में सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को गति देते हुए श्री महाकाल लोक के अन्नक्षेत्र पार्किंग परिसर में पीएम ई-बस सेवा तथा उज्जैन दर्शन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शक्ति पथ, महाकाल लोक से बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने राजाराम रिसोर्ट तक यात्रा भी की। इस अवसर पर वेदपाठी बटुकों के द्वारा वेद मंत्रों का वाचन किया गया और डमरू वादन भी किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि मैं भगवान श्री महाकालेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज उनकी नगरी में एक अद्भुत अलग प्रकार का दिन है। एक के बाद एक शहर को रोज एक नई सौगात मिल रही है। रोज नए प्रकार के विकास के कीर्तिमान बन रहे हैं। 21 साल पहले राज्य परिवहन निगम की बसें चला करती थीं, फिर किसी कारण से सार्वजनिक परिवहन बसों को बंद करना पड़ा। हमने वह अभाव आज पूरा किया है। राज्य परिवहन निगम की बसें एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगी। शहर के अंदर नगरीय स्तर पर भी बसें चलाई जाएंगी। उज्जैन में धार्मिक पर्यटन केंद्र के लिए 10 बसों की सौगात मिल रही है। हम सब इसमें यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा प्रदेशवासियों का सफर सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं ई-बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। उज्जैन में यह सेवा श्रद्धालुओं, पर्यटकों और नगरवासियों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी।

कार्यक्रम में सांसद श्री अनिल फिरोजिया,
राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी,
महाराज, डॉ लता वानखेडे, महापौर श्री मुकेश
टटवाल, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष
श्री ओम जैन, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण समिति
के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, श्री संजय
अग्रवाल, श्री विवेक जोशी, श्री राजेंद्र भारती,
श्री जगदीश पांचाल, श्री प्रभुलाल जाटवा,
एडीजी श्री राकेश गुप्ता, डीआईजी श्री नवनीत



भरसीन, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, कलेक्टर
श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री
प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस
कूमट, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष
मिश्रा, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री संदीप सोनी,
अधीक्षक यंत्री श्री के.ही.मालवीय एवं अन्य
गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

उज्जैन दर्शन मार्ग

उज्जैन दर्शन सेवा का निर्धारित मार्ग मेघदूत
वन पार्किंग से प्रारंभ होकर महाकाल लोक,
हरसिद्धि मंदिर, क्षिप्रा नदी, ऋणमुक्तेश्वर
महादेव, भर्तृहरि गुफा, गढ़ कालिका माता
मंदिर, काल भैरव मंदिर, सिद्धवट मंदिर,
अंगारेश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनि
आश्रम, भूखी माता मंदिर, चिंतामण गणेश
मंदिर, अष्ट विनायक मंदिर, शनि नवग्रह
मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बस स्टैंड एवं उज्जैन
रेलवे स्टेशन होते हुए पुनः मेघदूत वन पार्किंग
पर समाप्त होगा। इसका शुल्क 200 रुपये
मात्र होगा। यात्री यूपीआई के माध्यम से पेमेंट

कर सकेंगे। यह बसें पूर्ण रूप से जीरो एमिशन रहेंगी , इनसे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा और यह इलेक्ट्रिकल चार्ज होंगी। यह मार्ग उज्जैन के प्रमुख मंदिरों एवं पौराणिक स्थलों को एक श्रृंखला में जोड़ेगा। उज्जैन दर्शन रूट की कुल लंबाई 27.01 किलोमीटर है।

बस संचालन की व्यवस्था

यात्री निर्धारित स्टॉप पर बस से उतरकर संबंधित मंदिर या दर्शनीय स्थल का दर्शन करेंगे। सकेगें तथा दर्शन पूर्ण होने के बाद उसी स्टॉप से अगली उपलब्ध उज्जैन दर्शन बस में यात्रा जारी रख सकेगें। निर्धारित वैधता अवधि के दौरान एक ही टिकट पर यात्री मार्ग के विभिन्न स्टॉप से बस में चढ़ और उतर सकेगें। सभी प्रमुख मंदिरों एवं दर्शनीय स्थलों के निकट निर्धारित बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए बसों का संचालन नियमित अंतराल पर किया जाएगा। प्रत्येक प्रमुख स्थल पर दर्शन एवं भ्रमण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहेगा। यह सेवा

मेघदूत वन पार्किंग से प्रारंभ होकर प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को एक ही सेवा से प्रमुख दर्शन स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

આધુનિક સુવિધાएं

बसों में लाइव सीसीटीवी, जीपीएस आधारित लाइव ट्रेकिंग, डिजिटल टिकटिंग तथा यूपीआई/डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बस में डिजिटल असिस्टेंट सह उज्जैन दर्शन गाइड भी उपलब्ध रहेंगे, जो प्रमुख मंदिरों, दर्शनीय स्थलों, मार्ग एवं दर्शन संबंधी आवश्यक जानकारी देंगे।

प्रमुख दर्शन स्थल एवं मान्यता

महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक एवं उज्जैन का अधिष्ठाता

देव स्थल है। यहाँ की भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाकाल लोक शिव पुराण की कथाओं एवं शिव-स्वरूपों को मूर्तियों, स्तंभों और भित्तिचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। हरसिद्धि माता उज्जैन की प्राचीन शक्तिस्थली हैं। क्षिप्रा नदी के पवित्र घाटों पर स्नान एवं पूजा-अर्चना की मान्यता है। ऋणमुक्तेश्वर महादेव में पूजा से विभिन्न ऋणों से मुक्ति की मान्यता जुड़ी है।

भर्तृहरि गुफाएँ राजा भर्तृहरि की तपस्या एवं नाथ संप्रदाय की साधना परंपरा से जुड़ी हैं। गढ़ कालिका मंदिर की मान्यता महाकवि कालिदास से जुड़ी हुई है। काल भैरव उज्जैन के रक्षक देवता माने जाते हैं। सिद्धवट पितृ कर्मों के लिए विशेष तीर्थ है। अंगारेश्वर एवं मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह संबंधी मान्यताओं से जुड़े हैं। सांदीपनि आश्रम वह स्थल है जहाँ मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण, बलराम एवं सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। भूखी माता, चिंतामण गणेश, अष्ट विनायक, शनि नवग्रह एवं इस्कॉन मंदिर भी इस मार्ग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

नगर की अन्य बस मार्ग व्यवस्था

उज्जैन शहर में सुगम परिवहन के अंतर्गत कुल 12 मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिनमें तपोभूमि से पानबिहार, उज्जैन रेलवे स्टेशन से कालियादेह महल, कानीपुरा से अभिलाषा कॉलोनी, देवास गेट से तपोभूमि, देवास गेट से ताजपुर, देवास गेट से एफ आरटीओ कार्यालय, महाकाल चौराहा से अभिलाषा कॉलोनी, देवास गेट से नानाखेड़ा, अवंतिका विश्वविद्यालय से नानाखेड़ा, देवास गेट से मुरलीपुरा, तपोभूमि से नजरपुर तथा उज्जैन दर्शन मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों से नगर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक क्षेत्रों को बस सेवा से जोड़ा गया है। यह सेवा श्रद्धालुओं को महंगे निजी परिवहन पर निर्भरता घटाते हुए सुविधाजनक, किफायती और सुरक्षित दर्शन यात्रा उपलब्ध कराएंगे। सिंहस्थ-2028 को तैयारियों के दृष्टिगत उज्जैन में सुगम आवागमन की यह व्यवस्था नगरवासियों एवं देश-विदेश से आने वाले भक्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

अवंतिका का वैभव ही सदियों से रहा है इसका गौरव : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने उज्जैन को दी 173 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

कोबरा डॉट कोम | न्यूज

भोपाल, जरा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश के समान विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उज्जैन (अर्वातिका) एक प्राचीन नगर है। यहां का व्यापार व्यवसाय और इसका वैभव ही सदियों से इस नगर का गौरव और पहचान रही है। उज्जैनवासियों ने हर काल में शहर के विकास में सहयोग दिया है और आज भी यहां के लोग विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए स्वैच्छिक योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को महाकाल महालौक, उज्जैन में विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां 173 करोड़ रुपये लागत के 15 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन को जल्द ही मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। भोपाल के मास्टर प्लान का डॉम्प्ट प्रकाशित कर दिया गया है। ग्वालियर नई मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित होगा साथ ही इसे टेलीकॉम सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर-भोपाल-जबलपुर तक औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। हमारी सरकार सेवा भाव से समान रूप से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुगम परिवहन सेवा से प्रदेश में नई परिवहन सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। इसके अन्तर्गत



यात्री बसों एक नगर से दूसरे नगर तक ही नहीं, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाएंगी। उज्जैन में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए उज्जैन दर्शन हेतु 10 नई पीएम ई-बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम को उज्जैन सांसद श्री अनिल फिकरेजिया, राज्यसभा सदस्य बालयोगीश्वरी श्री उमेशनाथ महाराज, सांसद डॉ. लता वानखेडे एवं महापौर श्री मुकेश टटवाल ने भी संबोधित किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उज्जैन का चौमुखी विकास हो रहा है तथा सिंहस्थ के दृष्टिगत नगर को सजाया-संवारा जा रहा है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री ओम जैन, सिंहस्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र भारती, श्री संजय अग्रवाल, श्री जगदीश पांचाल एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। आरंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

उज्जैन में होंगे 173 करोड़ रुपए के विकास कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को

उज्जैन में हुए कार्यक्रम में 15 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 12 कार्यों का भूमि-पूजन और 3 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। भूमि-पूजन कार्यों में मुख्य रूप से नगर निगम उज्जैन के 8 बड़े कार्य हैं, जिनमें गौशाला मार्ग से शिप्रा विहार मार्ग निर्माण, महाकाल लोक क्षेत्र में पार्किंग सुविधा, श्री महाकाल मंदिर परिसर का विकास एवं क्षिप्रा नदी के घाटों का जीर्णोद्धार जैसे कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल मंदिर के पीछे लैंडस्केपिंग, पुलिस विभाग द्वारा चिंतामण जवासिया में पुलिस आवास और उन्हेल में थाना भवन तथा पर्यटन विभाग द्वारा 45 नगरीय वनों का विकास कार्य शामिल है, जिनकी कुल लागत 153.31 करोड़ रुपये है। लोकार्पित किए गए कार्यों में पुलिस आवास अधोसंरचना विकास निगम द्वारा नीलगंगा और उन्हेल में निर्मित पुलिस आवास एवं थाना भवन तथा ऊर्जा विभाग द्वारा बड़नगर में निर्मित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 19.56 करोड़ रुपये है। इन सभी कार्यों से उज्जैन के नागरिकों को अधोसंरचना, सुरक्षा और पर्यटन विकास की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

सेवा संकल्प अभियान के तहत “आंगन मिलन” कार्यक्रम का आयोजन

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

भोपाल। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के मुख्य आतिथ्य में “सेवा संकल्प अभियान” के अंतर्गत शाजापुर जिले के शुजालपुर के फ्रीगज राधवगंज आंगनवाड़ी केंद्र 20/1 में “आंगन मिलन” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थितजनों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “मन की बात” कार्यक्रम के 138वें संस्करण एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उद्बोधन का एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण हुआ।

कार्यक्रम में मंत्री श्री परमार ने आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित नन्हे-मुन्ने बच्चों एवं माताओं के साथ आत्मीय संवाद किया। इस दौरान मंत्री श्री परमार ने माताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं दैनिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी भी ली। मंत्री श्री परमार ने बच्चों के साथ समय बिताया तथा उनकी गतिविधियों में सहभागिता की। इस दौरान बच्चों की मासूमियत और उत्साह ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बच्चों को खिलोने की कठिन वितरित की गई। मंत्री श्री परमार ने कहा कि बच्चे हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य हैं। उनके स्वास्थ्य, शरीर, संस्कारित मन और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रारंभिक वर्षों में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सदृश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और संस्कारों से जोड़ने का कार्य किया जाता है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि आंगनवाड़ी केवल बच्चों की देखभाल और पोषण

का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने वाला महत्वपूर्ण केंद्र है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में परिवार के साथ समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब समाज संवेदनशील होकर बच्चों और माताओं के साथ खड़ा होता है, तो सेवा की भावना और अधिक मजबूत होती है।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर सेवा और सहभागिता की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदना और सहयोग पहुंचाना तथा जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही सेवा का वास्तविक उद्देश्य है। मंत्री श्री परमार ने माताओं से भी बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पौष्टिक आहार, स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य देखभाल तथा अच्छे संस्कार अत्यंत आवश्यक हैं। बच्चों के प्रारंभिक विकास में माता-पिता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने केंद्र में संचालित गतिविधियों तथा बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

उपस्थित माताओं ने भी बच्चों से जुड़े विषयों पर संवाद किया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ आत्मीय वातावरण में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि 'आंगन मिलन' कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों से जनभागीदारी को जोड़ना, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा माताओं और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद के माध्यम से सेवा एवं संवेदना की भावना को मजबूत करना रहा।

एलपीयू में बवाल: हॉस्टल का कमरा नंबर 503, यहीं से शुरू हुई कहानी, उस रूम की छात्राओं ने क्या बताया; चैट वायरल

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

नई दिल्ली। पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में शनिवार देर रात कथित दुष्कर्म की खबर ने ऐसा तूल पकड़ा कि देखते ही देखते सैकड़ों छात्र कैम्पस से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए और जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि जी-3 हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के साथ करीब तीन दिन पहले दुष्कर्म हुआ और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे उग्र हो गया और कैम्पस में तोड़फोड़ तथा आगजनी की घटनाएं सामने आईं।

छात्रों का दावा है कि कथित पीड़िता अब लापता है और यही सवाल प्रदर्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि यदि हॉस्टल में किसी छात्रा के साथ इतनी गंभीर वारदात हुई है तो वह छात्रा आखिर कहां है और उसकी शिकायत पुलिस तक क्यों नहीं पहुंची।

जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला के अनुसार रात करीब दो बजे बड़ी संख्या में छात्रों ने हाईवे जाम किया और उनकी मुख्य मांग जी-3 हॉस्टल की छात्रा के साथ कथित दण्डकर्म की जांच थी।

पुलिस का कहना है कि छात्रों की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कथित पीड़िता की पहचान, घटनास्थल और आरोपी के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर फगवाड़ा के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यदि वास्तव में दुष्कर्म हुआ है तो पुलिस पीड़िता की पहचान सामने आने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराएगी और आरोपी तक पहुंचने के लिए हर



हॉस्टल के कमरा नंबर 503 की कहानी

कथित दुष्कर्म की खबर
से कैंपस में तोड़फोड़

एलपीयू में हिंसा से पहले
की चैटिंग हुई वायरल

संभव जांच करेगी।

हॉस्टल के कमरा नंबर 503
में रहने वाली छात्राओं ने क्या
बताया?

मामले को लेकर एक और पेच यह है कि हॉस्टल के कमरा नंबर 503 में रहने वाली छात्राओं ने ऐसी किसी वारदात से इनकार किया है और कहा है कि उनके कमरे में ऐसी कोई घटना नहीं हुई तथा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं एलपीयू प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को झूठी और मनगढ़ंत अफवाह बताते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने के लिए भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जसपाल सिंह संधू ने कहा कि पुलिस ने छात्रों के आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की

है और विश्वविद्यालय जांच में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में पांच छात्रों को शामिल किया गया है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिल्महाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म होने का दावा किया जा रहा है, वह कौन है, घटना वास्तव में कहां हुई और अब तक वह पुलिस के सामने क्यों नहीं आई? एक तरफ सैकड़ों छात्रों के आरोप और विरोध प्रदर्शन हैं, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय इसे अफवाह बता रहा है और पुलिस के पास अभी कथित पीड़िता की स्पष्ट पहचान तथा घटना के ठोस विवरण का अभाव है।

ऐसे में अब पुलिस जांच, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल व अन्य साक्ष्यों और कथित पीड़िता की पहचान सामने आने के बाद ही साफ होगा कि एलपीयू में वास्तव में क्या हुआ



था। तब तक कथित दुष्कर्म को स्थापित तथ्य मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह आधी रात को विश्वविद्यालय में बवाल हुआ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल और तोड़फोड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हाईवे जाम हुआ और कैपस की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, उसने एलपीयू की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मैसेज से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में विवाद भड़क गया। मैसेज में दावा किया गया कि जी-3 गलर्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है और वह लापता है। मैसेज फ्लूटते ही छात्रों में आक्रोश फैल गया और 26-27 सितंबर की रात करीब दो बजे

बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल के बाहर जमा हो गए। इसके बाद कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव हुआ और छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस का भारी बल तैनात करना पड़ा। हालांकि जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला और फगवाड़ा के एसपी मेजर सिंह ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर चल रही दुष्कर्म और छात्रा के लापता होने की खबर की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में न तो कोई शिकायत मिली है और न ही किसी कथित पीड़िता की पहचान सामने आई है। मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे पर यातायात बिल्कुल ठप रहा और पुलिस व विद्यार्थियों के बीच तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

हिमाचल: शिमला में बारिश के बीच पहाड़ी से गिरा मलबा, जांगलिख पुल के पास लैंडस्लाइड से मचा हड़कंप; सड़क बंद



कोबरा डॉट कोम । न्यूज

नई दिल्ली। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बीच एक बार फिर भूस्खलन ने चिंता बढ़ा दी है। शिमला जिले के चिड़गांव क्षेत्र में जांगलियु पुल के पास सोमवार सुबह अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। देखते ही देखते सड़क पर मलबा और बड़े-बड़े पत्थर जमा हो गए और वाहनों की आवाजाही रुक गई। स्थानीय जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर रविवार से ही पहाड़ी से रुक-रुककर पत्थर गिर रहे थे। सड़क से गुजरने वाले लोगों को खतरे का अंदाजा हो गया था। सोमवार सुबह स्थिति अचानक बिगड़ी और पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक गया। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सड़क पर मलबा, दोनों तरफ यातायात प्रभावित

लैंडस्लाइड के बाद सड़क का बड़ा

हिस्सा मलबे से ढक गया। इसके चलते इस मार्ग से आने-जाने वाले वाहनों को आवाजाही प्रभावित हुई है। मौके पर प्रशासन की टीम स्थिति का आकलन कर रही है और रास्ते को सुरक्षित तरीके से खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

सुंदरू खड्ड का बहाव भी हुआ प्रभावित

भूखलन का असर पास की सुंदरू खडू पर भी पड़ा। मलबा खडू में पहुंचने के कारण पानी का बहाव कुछ समय के लिए बाधित हुआ। इस वजह से आसपास रहने वाले लोगों में पानी के अचानक बढ़ने को लेकर चिंता पैदा हुई। हालांकि, रोहडू के एसडीएम धर्मेश रमोत्रा ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी का बहाव अब दोबारा शुरू हो गया है और खडू में झील बनने जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने साथ ही अचानक जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी।

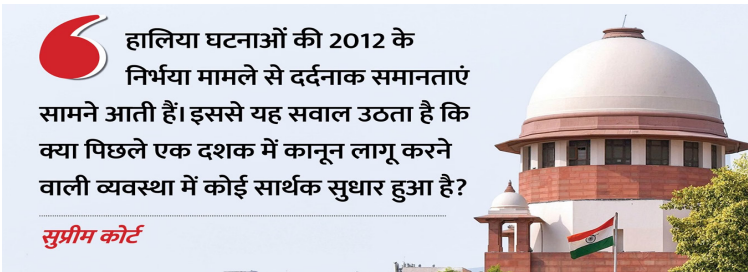
नदी-खड्ड से दूरी बनाए रखने की अपील

प्रशासन ने जांगलिख इलाके के साथ-साथ पब्वर नदी और आसपास की खुदों के किनारे अनावश्यक रूप से जाने से बचने को कहा है। बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का प्रवाह अचानक तेज हो सकता है, इसलिए स्थानीय लोगों और यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

बारिश ने बढ़ाई भूस्खलन की चिंता

शिमला और आसपास के इलाकों में सोमवार को मौसम खराब रहा और हल्की बारिश भी हुई। ऐसे में पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने भी बारिश के दौरान भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी रखने और नदी-नालों के पास सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि जंगलिख पुल के पास सड़क बाधित है, जबकि प्रशासन खड्ड के बहाव और सड़क की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर अदालत सख्त, कहा- निर्भया केस से हैं दर्दनाक समानताएं



कोबरा डॉट कोम । न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दुष्क्रम के हालिया मामलों और दिल्ली में चलती स्लीपर बस में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं से 2012 की निर्भया घटना की दर्दनाक यादें ताजा होती हैं। इनमें सार्वजनिक पार्क में एक किशोरी के साथ हुई हालिया घटना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं से कानून लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता साफ तौर पर सामने आती है। सार्वजनिक स्थानों, जिनमें कॉफी और बसें भी शामिल हैं, को रोशनी की कमी, निगरानी की कमजोरी व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव में जोखिम वाले क्षेत्र बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने की क्या टिप्पणी?

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कोर्ट की रजिस्ट्री को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल एकजुटता जताना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि जिम्मेदारी तय की जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। बार एंड बेंच की

रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “हालिया घटनाओं की 2012 के निर्भया मामले से दर्दनाक समानताएं सामने आती हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या पिछले एक दशक में कानून लागू करने वाली व्यवस्था में कोई सार्थक सुधार हुआ है।”

चलती बस में छात्रा से हुई थी
दरिंदगी

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसा कांड सामने आया। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस में यह वारदात हुई। बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर चालक और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपी चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 4 अगस्त 2026 की बताई गई है। वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पीड़िता मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। छात्रा 3 अगस्त 2026 को अपने घर से बिना बताए निकली थी। वह पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज थी। उसका इरादा नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जाने का था।

भोपाल Master Plan-2047 में बड़ा बदलाव, चौड़ी सड़क से प्लॉट कमर्शियल नहीं; 12% ओपन स्पेस जरूरी

कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

भोपाल। भोपाल के मास्टर प्लान-2047 के प्रस्तावित ड्राफ्ट में शहर के विकास और नई कॉलोनियों के स्वरूप को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब किसी भी नई कॉलोनी में महज सड़क चौड़ी होने से कोई प्लॉट कमर्शियल नहीं मान लिया जाएगा। इसके लिए लेआउट में स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा, कॉलोनियों में हरियाली और बच्चों के लिए खेल मैदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खुली जगह (ओपन स्पेस) का दायरा भी 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया है।

चौड़ी सड़क का मतलब सीधे कमर्शियल प्लॉट नहीं

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के अनुसार, नई कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई के आधार पर दुकान, ऑफिस, अस्पताल या मॉल खोलने की गुंजाइश तो दी है, लेकिन लेआउट पास करते

समय ही यह तय करना होगा कि कमर्शियल या मिक्स लैंड यूज के प्लॉट कहाँ होंगे। नई कॉलोनी में कुल आवासीय क्षेत्र के अधिकतम 5% हिस्से में ही स्थानीय जरूरतों वाली दुकानें खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, अगर सड़क 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी है, तो इस 5% की सीमा के अलावा भी मिक्स लैंड यूज वाले प्लॉट मंजूर किए जा सकेंगे। पहले से बसी पुरानी कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से कमर्शियल गतिविधियों की छूट मिलेगी, लेकिन आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय उपयोग स्वीकृत एफएआर (FAR) के अधिकतम 50% तक ही सीमित रहेगा।

हरियाली और खेल मैदानों पर विशेष जोर

नए प्रस्ताव में पर्यावरण और खुले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। नई कॉलोनियों में अब 12 प्रतिशत सामुदायिक खुली जगह छोड़ना अनिवार्य होगा, जिसमें से आधी जगह एक

साथ (सिंगल पैच में) रखनी होगी। इस कुल खुले क्षेत्र का 30 फीसदी हिस्सा पेड़-पौधों के लिए और 30 फीसदी बच्चों के खेल मैदान के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा, सर्विस सुविधाओं के लिए अलग से 2% जमीन छोड़ना भी अनिवार्य किया गया है।

शहर के बाहर व्यक्तिगत मकान बनाने पर सख्त हुए नियम

अक्सर लोग शहर के बाहर शांत इलाकों में बड़ी जमीन लेकर अपना अलग मकान बना लेते हैं, जिससे वहां सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का दबाव बढ़ जाता है। अब ऐसे व्यक्तिगत मकानों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। इनके लिए कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क का होना जरूरी है। साथ ही अधिकतम 25% ग्राउंड कवरेज, 10 मीटर ऊंचाई और 1.25 एफएआर (FAR) का प्रस्ताव रखा गया है। मकान मालिक को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उसकी जमीन किसी अवैध कॉलोनी का हिस्सा तो नहीं है।



छोटे प्लॉट वालों को मार्जिन में राहत

नक्शा पास कराते समय प्लॉट के चारों ओर छोड़ी जाने वाली जगह (मार्जिन) के नियमों में छोटे प्लॉट वालों को काफी राहत दी गई है। 517 वर्ग फीट तक के प्लॉट में सिर्फ सामने की तरफ 3 मीटर जगह छोड़नी होगी। पीछे या अगल-बगल कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। 517 से 1615 वर्ग फीट तक के प्लॉट में सामने 3 मीटर और पीछे 1.5 मीटर जगह छोड़नी होगी। 1615 से 2422 वर्ग फीट तक के प्लॉट में सामने 3 मीटर, पीछे 1.5 मीटर और एक तरफ 3 मीटर जगह छोड़नी होगी। इससे बड़े आकार (5382 वर्ग फीट तक) के प्लॉट्स के लिए साइज के हिसाब से चारों तरफ

जगह छोड़ने के अलग-अलग नियम तय किए गए हैं। दूसरी ओर, सामान्य आवासीय प्लॉट्स पर निर्माण की अच्छी छूट दी गई है। मसलन, 5000 वर्ग फीट के प्लॉट पर सभी मंजिलों को मिलाकर 7500 वर्ग फीट तक निर्माण किया जा सकता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 12.50 मीटर हो सकती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 फ्लैट बनाने की इजाजत होगी।

अतिरिक्त निर्माण के लिए टीडीआर (TDR) और शुल्क का फॉर्मूला

अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से अधिक निर्माण करना चाहता है, तो उसे अतिरिक्त एफएआर का 50% हिस्सा शुल्क देकर और बाकी 50% हिस्सा टीडीआर (यानी दूसरे की जमीन से मिला निर्माण अधिकार) के जरिए हासिल करना होगा। वहीं, 12.50 मीटर तक की ऊंचाई वाले मकानों में एफएआर को 1.25 से बढ़ाकर 1.50 तक ले जाने के लिए पूरा अतिरिक्त अधिकार शुल्क देकर मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।

श्योपुर: कूनो के चीतों का अब हाईवे पर होगा प्रचार, राजस्थान-एमपी और यूपी के प्रमुख मार्गों पर लगेंगे साइन बोर्ड



कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौजूदगी अब बाहर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ उनकी राह भी आसान करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के मार्गों पर चीते की तस्वीर वाले सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएंगे। इन पर कूनो नेशनल पार्क की दूरी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। उद्देश्य इन शहरों से गुजरने वाले यात्रियों

और पर्यटकों को कूनो की जानकारी देना है ताकि वे वन्यजीव पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश में श्योपुर की ओर आसानी से रुख कर पाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने की इस पहल के अंतर्गत ऐसे स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां से बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों और पर्यटन स्थलों की ओर आवागमन करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की इस पहल के अंतर्गत ऐसे स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां से बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों और पर्यटन स्थलों की ओर आवागमन करते हैं।

MP Police Band Result 2026: 39 हजार युवाओं का इंतजार खत्म, 591 की जगह 560 पदों पर चयन

कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक (बैंड) भर्ती-2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने तमाम विवादों और हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं के बीच इस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। नियमों के तहत 87 फीसदी मुख्य भाग के आधार पर कुल 560 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 591 की जगह 560 पदों पर ही तयों आई सूची?

चयन प्रक्रिया के 87% फार्मूले (जिसमें 14% ओबीसी पद भी शामिल हैं) के हिसाब से कुल 591 पदों पर रिजल्ट जारी होना था। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में तय न्यूनतम योग्यता को पार करने वाले पर्याप्त उम्मीदवार ही नहीं मिल सके। योग्य अभ्यर्थियों की इसी कमी के कारण विभाग को 591 के बजाय केवल 560 पदों पर ही चयन सूची जारी करनी पड़ी।

नतीजे तय करने में अपनाए गए ये तीन अहम नियम

परिणाम जारी करते समय पुलिस मुख्यालय ने तीन प्रमुख बातों का ध्यान रखा है... उम्र से सुलझा टाई: अगर दो या उससे

अधिक उम्मीदवारों के अंक बराबर आए हैं, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता देकर चुना गया है। ओपन वर्ग से भरी गई खाली सीटें: भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड कोर्ट में जब पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, तो नियमानुसार उन खाली पदों को उसी श्रेणी के सामान्य (ओपन) उम्मीदवारों से भर दिया गया है। कोर्ट के फैसले पर टिका रहेगा भविष्य: यह परिणाम पूरी तरह से अंतिम नहीं है। जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर खंडपीठ में इस भर्ती से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में यह परिणाम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। इसके साथ ही, रिजल्ट में किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी सामने आने पर पुलिस मुख्यालय के पास उसे सुधारने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखा गया है। पुलिस विभाग में सामान्य आरक्षक से लेकर नाई, धोबी और कुक जैसे ट्रेड पदों के लिए भी लिखित परीक्षा के साथ-साथ फिजिकल टेस्ट (800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक) देना अनिवार्य होता है। लेकिन बैंड आरक्षक भर्ती में ऐसा कोई नियम नहीं था। इसमें चयन का आधार सिर्फ वाद्ययंत्र बजाने की कला और इंटरव्यू को बनाया गया था। इसी प्रक्रिया को लेकर कई उम्मीदवारों ने शुरुआत से ही सवाल उठाए और चयन में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

ग्वालियर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) परीक्षा भले ही अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन सीबीएसई स्कूलों में इसकी तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की 2026-27 मुख्य बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने स्कूलों से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) जमा करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पैटर्न को समझने का एक अहम माध्यम सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम भी चर्चा में है।

सैंपल पेपर को केवल परीक्षा से पहले अभ्यास के लिए हल करने वाला पेपर समझना विद्यार्थियों की तैयारी को सीमित कर सकता है। इसमें प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नपत्र का डिजाइन और पाठ्यक्रम के विभिन्न हिस्सों को किस तरह पूछा जा सकता है, इसकी व्यापक समझ मिलती है।

सीबीएसई स्वयं सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम को प्रश्नपत्र के डिजाइन तथा पाठ्यक्रम की उचित कवरेज के लिए मार्गदर्शक बताता रहा है। विद्यार्थियों के लिए चार काम जरूरी सैंपल पेपर को निर्धारित समय में हल करें। हल



करने के बाद मार्किंग स्कीम से अपने उत्तरों का मिलान करें। जिन प्रश्नों में बार-बार गलती हो रही है, उनकी अलग सूची बनाएं।

स्कूल में जमा होने वाले एलओसी में अपना नाम, विषय और अन्य विवरण सही हैं या नहीं, इसकी पुष्टि करें।

सिर्फ प्रश्न हल करना पर्याप्त नहीं

सहोदय कॉम्प्लेक्स के संरक्षक विनय झलानी के अनुसार, विद्यार्थी सैंपल पेपर हल करने के बाद मार्किंग स्कीम जरूर देखें। इससे पता चलता है कि किसी उत्तर में किन बिंदुओं को महत्व दिया गया है। खासकर

लंबे उत्तर वाले विषयों में विद्यार्थी कई बार जानकारी तो पूरी लिख देते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार उत्तर को व्यवस्थित नहीं कर पाते। मार्किंग स्कीम देखकर वे यह समझ सकते हैं कि उत्तर में मुख्य बिंदु, अवधारणा, उदाहरण या आवश्यक चरण किस तरह प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परीक्षा संगम पर सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन बैंक और मॉडल आंसर जैसी परीक्षा संबंधी सामग्री के लिए अलग व्यवस्था उपलब्ध कराई है।

एलओसी में छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी

बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ स्कूलों में विद्यार्थियों का परीक्षा संबंधी डेटा भी तैयार किया जा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं 2026-27 के लिए एलओसी जमा करने की प्रक्रिया संबंधी सर्कुलर 21 सितंबर को जारी किया था। इस चरण में विद्यार्थियों के नाम, विषय और अन्य विवरणों की शुद्धता महत्वपूर्ण है। सीबीएसई के पिछले एलओसी निर्देशों में भी विषय संबंधी विवरण को सावधानी से भरने पर जोर दिया गया था, क्योंकि बाद में विषय परिवर्तन से जुड़ी मांगें स्वीकार नहीं की जातीं।

भोपाल में SIR के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, दिग्विजय सिंह बोले- निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत

कोबरा डॉट कोम ।न्यूज़

भोपाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निर्वाचन सदन तक पैदल मार्च किया। कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर देश भर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने का गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निर्वाचन सदन तक पैदल मार्च मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरोध में आयोजित कांग्रेस के इस प्रदर्शन में अभी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय (निर्वाचन सदन) तक गए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप



है कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर देश के लगभग 13 करोड़ मतदाता भाइयों के नाम काट दिए गए हैं। यही पार्टी की मुख्य शिकायत है। नेताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि आज पूरे देश में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जब से ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग

का पद संभाला है, तब से हालात खराब हैं। उन्होंने बताया कि संधू जी और जोशी जी ने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि चुनाव आयोग द्वारा जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई, वह ठीक नहीं थी। दिग्विजय सिंह ने जोर देते हुए कहा कि किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बेहद आवश्यक है।

फर्जी दस्तावेजों से खुद को शहर काजी घोषित कराने का प्रयास, सांवेर पुलिस ने दर्ज किया केस

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

इंदौर। सांवेर पुलिस ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को तहसील सांवेर का शहर काजी घोषित कराने का प्रयास करने के आरोप में मोहम्मद सलामुद्दीन बरकाती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए कथित तौर पर असत्य आधार पर न्यायालयीन आदेश का उपयोग किया और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। इन दस्तावेजों के जरिए स्वयं को सांवेर का शहर काजी स्थापित कराने का प्रयास किए जाने का आरोप है। मामले में कलेक्टर कार्यालय, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच रिपोर्ट तथा पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में आरोपी द्वारा प्रस्तुत



दस्तावेज और दावे प्रथम दृष्टया मिथ्या, भ्रामक एवं नियम विरुद्ध पाए जाने की बात सामने आई। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण से प्राप्त अनुमोदन के बाद 24 सितंबर 2026 को सांवेर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रकरण में विवेचना शुरू कर दी है और दस्तावेजों की जांच के साथ अन्य साक्ष्य जुटाए

जा रहे हैं। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण राजेशकुमार वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी सांवेर देवेन्द्र सिंह धुर्वे के निर्देशन में की जा रही है। थाना प्रभारी सांवेर लाखन सिंह राजपूत और पुलिस टीम तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

राजवाड़ा पर नई-नवेली सिटी बस ने तीन लोगों को कुचला, एक की मौत; दो गंभीर

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

इंदौर। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में रविवार को एक नई-नवेली भगवा रंग की सरकारी सिटी बस की चपेट में आने से तीन लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं।

दुर्घटना के बाद मौके पर गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। हादसे के तुरंत बाद सभी को आनन-फानन में एमबाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। पुलिस आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से मृतकों और घायलों की पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने सबसे पहले बस के भीतर फंसी सवारियों को सुरक्षित बाहर



निकाला और फिर बस पर पथराव करते हुए उसके कांच फोड़ दिए। राजवाड़ा जैसे व्यस्त इलाके में हंगामे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए भीड़ को हटाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। एमजी रोड थाना प्रभारी विजय सिसौदिया से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा सिटी बस चालक की गफलत और लापरवाही के कारण घटित हुआ। अनियंत्रित बस अचानक सड़क से



गुजर रहे पैदल यात्रियों पर चढ़ गई, जिससे चारों लोग उसकी चपेट में आ गए। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना के समय बस की रफ्तार कितनी थी और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ।

इंदौर में 40 लाख की 9360 गर्भपात किट मिलीं, धारकोठी स्थित गोदाम पर हुई कार्रवाई से मिले सुराग

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

इंदौर। लसूडिया मोरी स्थित मोदी ब्रदर्स एसोसिएट्स पर शनिवार को औषधि विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान फर्म के गोदाम में सेफ-टी किट की 9360 किट मिलीं।

संबंधित फर्मों और प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी गई है

विभाग के अनुसार इनकी बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये है। औषधि निरीक्षक योगेश गुप्ता, लोकेश गुप्ता और सारिका अग्रवाल की टीम ने फर्म के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की जांच की। फर्म की ओर से कुछ ही विक्रय रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए। उपलब्ध दस्तावेजों में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से संबंधित बिल मिले।

इनकी जानकारी मुख्यालय भोपाल भेजी गई। इसके बाद औषधि नियंत्रक के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में संबंधित फर्मों और प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी गई है।

विभाग इन किट के क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेजों और बिलों का सत्यापन कर रहा है

प्रारंभिक रिकॉर्ड की जांच में फर्म द्वारा करीब 1 लाख 75 हजार सेफ-टी किट की खरीद और बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई है। अब विभाग इन किट के क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेजों और बिलों का सत्यापन कर रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि किट किन जिलों और किन प्रतिष्ठानों तक पहुंची। अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार



कार्रवाई की जाएगी। करीब दो दिन पहले धारकोठी स्थित गोदाम पर हुई औषधि विभाग की कार्रवाई के दौरान मिले सुराग के आधार पर ही लसूडिया मोरी स्थित फर्म तक जांच पहुंची थी। इसके बाद अब पूरे प्रदेश में कार्रवाई जारी है।

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

इंदौर। होलकर साइंस कॉलेज में कल गणपति विसर्जन समारोह में हुआ जमकर बवाल हुआ। ये छात्र करणी सेना और अभाविप के कार्यकर्ता हैं। इनके बीच जमकर मारपीट की गई। दोनों गुटों में बेल्ट और डंडे चले।

विवाद में बीएससी-एमएससी के कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। कॉलेज प्रबंधन ने अनुशासन समिति की बैठक रखी और विवाद में शामिल सात विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया है। मामले में भंवरकुआं थाने में भी एक पक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है। कॉलेज परिसर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम के अंतर्गत चल समारोह निकाला गया। इस दौरान दो गुटों में जमकर बहस हुई। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच करणी सेना और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी आए। दोनों संगठन ने एक-दूसरे कार्यकर्ताओं को

पार्किंग एरिया में बेल्ट से पिटाई की। बावजूद इसके विवाद और बढ़ गया और फिर कम्प्यूटर लैब में भी मारपीट की गई। विद्यार्थियों के मुताबिक कॉलेज में करणी सेना सक्रिय हो गई है। इसलिए आए दिन दोनों संगठन विद्यार्थियों को धमकाते हैं। कई बार ये आपस में विवाद करते हैं।

कॉलेज प्रशासन ने अनुशासन समिति की बैठक बुलाई

मारपीट की घटना के बाद एबीवीपी के दबाब में कॉलेज प्रशासन ने अनुशासन समिति की बैठक बुलाई। समिति ने घटना से संबंधित शिकायतों के साथ मौके के वीडियो फुटेज को बारीकी से देखा। समिति ने मारपीट की घटना को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए सात विद्यार्थियों के तत्काल निलंबन की अनुशंसा की। हर्ष तिवारी (पीजीडीसीए), अभिजीत सिंह



राजपूत, संस्कार यादव, हरिओम खाती (पटेल), अर्पित खाती (पटेल), भावन सिंह राजपूत और सत्यम शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन ने कहा कि अनुशासन समिति के अनुशंसा के बाद सात विद्यार्थियों को निलंबित किया है। कॉलेज ने निलंबन अवधि में इन सभी छात्रों का परिसर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही संबंधित छात्रों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) घर भेजे जाएंगे। कॉलेज परिसर में हुए विवाद के बाद मामला भंवरकुआं थाने तक भी पहुंच गया है। एक पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस स्तर पर मामले की जांच की जा रही है। जबकि दूसरे पक्ष ने आवेदन नहीं दिया है।

मुंबई सेंट्रल-बांद्रा से धौलपुर और उधना से कानपुर के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें, यात्रियों को होगी सुविधा

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

रतलाम। रेल प्रशासन यात्रियों की मांग को देखते हुए विशेष किराये पर तीन स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन 09007/09008 मुंबई सेंट्रल-धौलपुर स्पेशल दो, छह अक्टूबर को मुंबई और तीन, सात अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी। रतलाम में दोनों दिशाओं में इसका ठहराव रहेगा। बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी व आगरा कैंट इसके प्रमुख ठहराव होंगे। इसमें एसी श्री-टियर, स्लीपर व सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस-धौलपुर स्पेशल सात अक्टूबर

को बांद्रा तथा आठ अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस-धौलपुर स्पेशल सात अक्टूबर को बांद्रा तथा आठ अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी। ट्रेन 04168/04167 उधना-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार उधना तथा दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार कानपुर से चलेगी। रतलाम : रेल प्रशासन यात्रियों की मांग को देखते हुए विशेष किराये पर तीन स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन 09007/09008 मुंबई सेंट्रल-धौलपुर स्पेशल दो, छह अक्टूबर को मुंबई और तीन, सात अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी। रतलाम में दोनों दिशाओं में इसका ठहराव रहेगा।

बड़वानी में छात्राओं का पैदल मार्च, छात्रावास में पेयजल, भोजन, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी

कोबरा डॉट कोम । न्यूज

बड़वानी। धोबड़िया तालाब के समीप कैलाश नगर स्थित शासकीय वीरांगना संयुक्त बालिका छात्रावास की छात्राएं शनिवार को छात्रावास की विभिन्न समस्याओं को लेकर करीब दो किमी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। छात्राओं ने पेयजल, भोजन, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने पर छात्राएं कुछ देर नाराजगी जताते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ही खड़ी रहीं। बाद में वे बाहर निकलकर वीआईपी मार्ग पर सड़क किनारे पेड़ की छांव में रुकी रहीं। छात्राओं के कलेक्ट्रेट पहुंचने की जानकारी मिलने पर एसडीएम भूपेंद्र रावत और सहायक आयुक्त

जनजाति कार्य विभाग रंजना सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्राओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि छात्राएं कलेक्टर से सीधे मुलाकात करने की मांग पर बनी रहीं।

छात्राएं सड़क किनारे पेड़ की छांव में रुकी रहीं

छात्राओं को छात्रावास वापस भेजने के लिए वाहन की व्यवस्था किए जाने की बात भी सामने आई, लेकिन छात्राएं वाहन से जाने के बजाय पैदल ही वापस निकल पड़ीं। कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर आने के बाद छात्राएं वीआईपी मार्ग पर सड़क किनारे पेड़ की छांव में रुकी रहीं। इससे अधिकारियों को दोबारा मौके पर पहुंचकर छात्राओं से चर्चा करनी पड़ी।

मोबाइल फोन पर कलेक्टर से बात करवाई

एसडीएम और सहायक आयुक्त ने छात्राओं की मोबाइल फोन पर कलेक्टर जयति सिंह से बातचीत कराई। छात्राओं ने कलेक्टर के सामने छात्रावास की समस्याएं रखीं। बातचीत के दौरान समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद छात्राएं वापस जाने के लिए तैयार हुईं और पैदल ही रवाना हो गईं। छात्राओं ने छात्रावास में पेयजल की समस्या के अलावा भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी शिकायत की। छात्राओं का आरोप है कि भोजन में कई बार सब्जियों में कीड़े निकलते हैं और खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है।